• ESTIMATES COMMITTEE

FIFTY-SIXTH REPORT

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal) : I beg to present the Fifty-sixth Report of the Estimates Committee regarding action taken by Government on recommendations contained in the Ninety-third Report of the Estimates Committee (Third Lok Sabha) on the Ministry of Home Affairs—Public Services.

12.13HRS.

STATEMENT BY MEMBER UNDER DIRECTION 115 AND MINISTER'S REPLY THERE TO

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विदेश मंत्रालय में उपमंत्री श्री सुरेन्द्रपाल सिंह जी ने 7 अगस्त, 1968 को लोक-सभा में श्री रविराय और मेरे प्रश्न के उत्तर में एक गलत और गुमराह करने वाला जवाब दिया। जब श्री रविराय ने उनसे पूछा कि "16 जून, 1968 को 'आबजरवर' में जो लेख निकला और जब भारत सरकार को पता चला कि इस तरह के इल्जाम लगाये गये हैं तो क्या भारत सरकार की ओर से 'आबजरवर' के सम्पादक को उस चीज का खण्डन करने के लिए कोई चिट्ठी भेजी गयी ? यदि हां, तो कब भेजी गई और कोई खण्डन छपा या नहीं ?" इस प्रश्न के उत्तर में श्री सुरेन्द्रपाल सिंह जी ने कहा कि "इस अखबार में शाया होने के बाद हमारी तरफ से लिखा गया। कब लिखा गया इसकी इत्तिला नहीं है, लेकिन मालूम हुआ कि हमारे वर्जन को छापने के लिए उन्होंने मना कर दिया।"

इसी प्रश्न के ऊपर मैंने निम्नलिखित सवाल पूछा :—"अभी मंत्री महोदय ने कहा कि उन्होंने 'आबजरवर' को लिखा लेकिन उन्होंने छापा नहीं। मुझे मलूम है कि 'आबजरवर' में जो बहुत से आर्टिकिल निकले उनके अलावा भी कई अखबारों में और ब्रिटिश प्रेस में इसके बारे में यह इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि नागलैंड में एक तरह से वियतनाम जैसी लड़ाई हो रही है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारे हाई कमीशन ने वहां पर किसी प्रकार से इस प्रोपेगन्डा को कन्ट्रडिक्ट किया है ? अगर किया है तो किस तरह से किया है ?" श्री सुरेन्द्रपाल सिंह जी ने उत्तर दिया 'आबजरवर' के बारे में तो मैं यह अर्ज करूं कि इस अखबार ने तो अन्डरग्राउन्ड नागाज को अपना काज बना लिया है और वे उनकी पूरी इमदाद कर रहे है। अब रही वहां के दीगर, अखबारों की बात, तो उनमें कभी कभी ऐसे आर्टिकिल निकलते है जो कि उनके फेवर में होते है और हमारे खिलाफ पड़ते है। लेकिन हमारे हाई कमिश्नर ने हमेशा उनका विरोध किया है और उनको बतलाया है और समझाया है। श्री सुरेन्द्रपाल सिंह जी ने आगे कहा कि जहां तक 'आबजरवर' का सवाल है उन्होंने जो कुछ कहा है वे कभी मानने के लिए तैयार नहीं है। इस अखबार में तो उन्होंने अपना काज बना लिया। हमने जो उनको भेजा था उसको उन्होंने पब्लिश भी नहीं किया"।

इससे यह बात स्पष्ट है कि उप मंत्री महोदय ने स्पष्टतया यह बात कही कि लन्दन स्थित भारतीय हाई कमिश्नर ने 'आबजरवर' में 16 जून, 1968 को छपने वाले लेख का खण्डन किया और उन्होंने उस लेख का खण्डन करते हुए पत्र 'आबजरवर' को भी लिखा, लेकिन 'अबजरवर' ने उसे नहीं छापा। यही बात उन्होंने मेरे प्रश्न के उत्तर में भी दोहराई और कहा कि उस अखबार ने हमारा वर्जन नहीं छापा और आबजरवर ने तो बागी नागाओं के काज को अपना काज बना लिया है।

इसके पश्चात् 'आबजरवर' ने 11 अगस्त, 1968 को एक समाचार छापा जिसका कुछ अंश निम्नलिखित हैं :—

The Indian Government last week launched an attack on the *Observer* during a debate in the Indian Parliament on the troubles in Nagaland. The Deputy External Affairs Mini-

[श्री कंवर लाल गुप्त]

ster Shri Surinder Pal Singh said "The *Observer* have made the Naga underground their cause and are giving them their Assistance." He alleged that the Indian High Commission in London had written to this paper contradicting two articles published last June about conditions along India's frontiers, but the *Observer* was not prepared to publish our replies.

The Indian High Commissioner in London has confirmed that no such letter was sent to the *Observer*. A letter received last Friday is published today on page 19.

इससे यह बात और स्पष्ट है कि 7 अगस्त, 1968 को जब उप मंत्री महोदय ने इस प्रश्न का उत्तर दिया उस समय तक हमारे लन्दन स्थित दूतावास की तरफ से ऐसा कोई भी पत्र 'आबज़रवर' को नहीं लिखा गया जिसमें 16 जून के लेख का खण्डन किया गया हो। वास्तव में उप मंत्री महोदय के उत्तर देने के बाद 'आबज़रवर' को पत्र भेजा गया और जिसे 'आबज़रवर' अखबार ने 11 अगस्त, 1968 को नवें पृष्ठ पर छापा है।

इसमें यह बात भी साफ हो गयी है कि इस समाचार पत्र ने कभी भी हमारे दृष्टिकोण को छापने से मना नहीं किया। जब इस समाचार पत्र को अपना दृष्टि कोण भेजा ही नहीं जाता तो छापने का प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमन्, यह बात अब स्पष्ट हो गई है कि उप मंत्री महोदय ने जानबूझ कर मेरे प्रश्न का गलत उत्तर दिया तथा सदन को गुमराह किया। इस प्रकार के गलत उत्तर देने से हमारे देश की तथा इस सदन की प्रतिष्ठा को धक्का लगता है जैसा कि इस केस में हुआ। जब 'आबज़रवर' ने 11 अगस्त को यह लिख दिया कि हमें भारतीय दूतावास की तरफ से कोई भी पत्र नहीं मिला और इसी समाचार को 'अमृत बाजार पत्रिका' ने 14 अगस्त को भी छापा जिसका शीर्षक था,

"U.K. Paper Accuses India Govt."

इससे यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि इंडियन हाई कमिश्नर ने भारत सरकार को कभी नहीं कहा कि उन्होंने कोई पत्र 'आबज़रवर' को लिखा है। ऐसा लगता है कि जब इनको मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं सूझा तो इन्होंने अपने तथा अपने विभाग को बचाने के लिए गलत और गुमराह करने वाला उत्तर दे दिया। वास्तव में यह प्रजातंत्र की पद्धति के विरुद्ध है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उप मंत्री महोदय से कहें कि वह 7 अगस्त को सदन में दिए गए उत्तर को ठीक करें।

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH): With your permission, may I submit that it was not my intention to make any statement deliberately to mislead the House in any manner. I regret if I gave any such impression in regard to the exchanges that took place during supplementaries on 7th August, 1968 following my answer to the Starred Question No. 362.

Sir, I should like to explain that what I had in mind was the continuous anti-Indian approach of the *Observer* in regard to Nagaland over the past several years. In spite of direct approaches to the Editorial staff of this newspaper by our senior officers in the High Commission, this newspaper has, particularly since 1961, adopted a biased approach on this question.

Infontation concerning Nagaland was sers to the *Observer* by our High Commision in London in our INDIAGRAM on 10th and 18th June, 20th and 25th July, 5th and 7th August, as well as through our India Weekly on 13th, 20th and 27th June, 4th, 11th and 25th July, and on 1st and 8th August. The *Observer*, however, took no note of this information. A letter sent to them on the14h of January 1966 by our Public Relations Officer in London was not published. It was against this background that I made my observations in reply to the supplementaries. I would invite the attention of this House to the fact

that it was only after the answer that I gave in the House on 7th August that the *Observer* published a letter of our Public Relations Officer on the 11th August for the first time after a very long time.

I hope this background will clear any misunderstanding I may have created in the minds of some Hon'ble Members for which I once again express regret.

SHRI HEM BARUA (Mangaldai) : I had also written to you about this. This London *Observer* is consistently pursuing an anti-India posture. This paper has not excused India becoming free. In its article by Colin Legnum published on 11 August, It has called the problem of Naga hostiles as a 'problem of minority'. It is not a problem of minority. But unfortunately, our London High Commission was sleeping over this matter all through. It did not contradict the articles published in the *Observer* during June. Would you not direct the Minister to take action against the High Commissioner ?

12.18 HRS.

PUNJAB STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL*

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : I beg to move for leave to introduce a Bill to confer on the President the power of the Legislature of the State of Punjab to make laws.

MR. SPEAKER : The question is : "That leave be granted to introduce a Bill to confer on the President the power of the Legislature of the State of Punjab to make laws."

The motion was adopted.

SHRI Y. B. CHAVAN : I introduce the Bill.

MOTION UNDER RULE 338 IN RESPECT OF FOREIGN MARRIAGE BILL

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW (SHRI M. YUNUS SALEEM) : I beg to move : "That rule 338 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in its application to the motion for concurrence in the recommendation of Rajya Sabha for reference of the Foreign Marriage Bill, 1963, to a Joint Committee, adopted by Lok Sabha on the 13th August 1968, be suspended".

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Why? Without any explanation ?

MR. SPEAKER : One Member is being substituted by another. The question is :

"That rule 338 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in its application to the motion for concurrence in the recommendation of Rajya Sabha for reference of the Foreign Marriage Bill, 1963, to a Joint Committee, adopted by Lok Sabha, on the 13th August 1968, be suspended.

The motion was adopted.

MOTIONS RE: JOINT COMMITTEE ON FOREIGN MARRIAGE BILL

THE DEPUTY MINISTRY IN THE MINISTRY OF LAW (SHRI M. YUNUS SALEEM): I beg to move: That the decision taken by Lok Sabha on the 13th August, 1968, on the motion for concurrence in the recommendation of Rajya Sabha for reference of the Foreign Marriage Bill, 1963, to a Joint Committee, be rescinded".

MR. SPEAKER : The question is :

"That the decision taken by Lok Sabha on the 13th August, 1968, on the motion for concurrence in the recommendation of Rajya Sabha for reference of the Foreign

*Published in Gazette of India Extra ordinary, Part II, Section 2, dated 28-8-68.